बड़ा सोचें, बड़े की चाहत रखें : गोयल

केंद्रीय मंत्री बोले– भारत की ग्रोथ का भविष्य एमएसएमई की ताकत से तय होगा

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सरकार की तरफ से मदद का पूरा आश्वासन देते हुए उनसे बड़ा सोचना और बड़े की चाहत रखने की अपील की है.

श्री गोयल ने सोमवार रात एमएसएमई संगठन सीआईएमएसएमई के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के भावी विकास का निर्णय एमएसएमई की मजबूती के आधार पर तय होगा. उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के उद्यमों के लिए दुनिया के विकसित देशों के बड़ बाजारों के दरवाजे खोल रही है. उन्होंने संगठन से अपने सदस्यों की इस प्रकार मदद करने की अपील की जिससे सूक्ष्म उद्यम लघु उद्यम बने सकें, लघु उद्यम मझौले और मझौले उद्यम बड़े बन सकें.

श्री गोयल ने कहा कि मोदी सरकार बनने के एक साल के भीतर मुद्रा योजना लायी गयी. कोरोना महामारी के समय सरकारी गारंटी पर एमएसएमई को सस्ता ऋण दिया गया. ठेले-खोमचे लगाने वालों के लिए छोटे ऋण वाली स्वनिधि योजना लाई गयी. उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय भारत की तरफ देख रही है. इस समय देश की अर्थव्यवस्था चार लाख करोड़ डॉलर की है और साल 2047 तक हम आठ गुना बढ़कर 30-35 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जायेंगे.

उन्होंने कहा, बड़ा सोचें, बड़े की चाहत रखें. न्यूजीलैंड के साथ सोमवार को संपन्न मुक्त व्यापार संधि (एफटीए) का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इससे सबसे ज्यादा फायदा एमएसएमई सेक्टर को होगा. पिछली सरकारों और मौजूदा सरकारों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बैंक बड़े उद्यमियों को सस्ता कर्ज देते थे और बड़े ऋण की वसूली में भी दिक्कत आती थी. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हर साल 80 हजार करोड़ रुपये का संयुक्त नुकसान हो रहा था. एनपीए, पुनर्गठित ऋण और फंसी हुई परिसंपत्ति मिलाकर 10 प्रतिशत से अधिक थी. वहीं, इसकी भरपाई एमएसएमई और अन्य छोटे ऋण लेने वालों पर ऊंचा ब्याज लगाकर की जाती थी. उन्हें 18-20 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था.

नोएडा एयरपोर्ट की साइबर सिक्योरिटी संभालेगी टेक महिंद्रा

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर. उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने नेटवर्क को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा ऑपरेशन के लिए महिंद्रा समूह की कंपनी टेक महिंद्रा के साथ करार किया है. दोनों कंपनियों की संयुक्त इस उद्देश्य के लिए टेक महिंद्रा एकीकृत नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर स्थापित करेगी. यह हवाई अड्डे पर निर्बाध और सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करेगा. टेक महिंद्रा नेटवर्क और हवाई अड्डे के आईटी ढांचे के लिए 24 गुना 7 निगरानी एवं प्रबंधन मुहैया करायेगी. इसमें एप्लिकेशन्स, डाटाबेस, नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज सिस्टम और संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल होंगे.

सोना-चांदी में तेजी, ग्राहकों की बढ़ी चिंता

1.36 रुपए पार हुआ सोना

2.09 रुपए के ऊपर पहुंची चांदी

नई दिल्ली, 23 दिसंबर 2025. देश में सोने और चांदी की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाते हुए आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ा दिया है. मंगलवार को बुलियन बाजार में दोनों कीमती धातुओं में तेज़ उछाल दर्ज किया गया. 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1 लाख 36 हजार रुपये के पार पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत भी 2 लाख 9 हजार रुपये प्रति किलो से ऊपर निकल गई.

लगातार बढ़ते दामों ने न सिर्फ आभूषण खरीदारों बल्कि निवेशकों की रणनीति को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, एक ही दिन में सोने और चांदी दोनों में उल्लेखनीय तेजी देखी गई. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों, डॉलर में कमजोरी और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते कीमती धातुओं में यह उछाल बना हुआ है. मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी के भाव में लगातार दूसरे दिन मजबूती देखने को मिली. 24 कैरेट शुद्ध सोना (999) प्रति 10 ग्राम 1,36,133 रुपये पर पहुंच गया, जो सोमवार शाम के मुकाबले 2,163 रुपये महंगा है.

> आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को 999 शुद्धता वाले सोने का सुबह का रेट 1,33,584 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो शाम तक बढ़कर 1,33,970 रुपये हो गया. मंगलवार को इसमें और तेजी आई और भाव 1.36 लाख के पार निकल गया. बाजार जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक अनिश्चितता, महंगाई की चिंता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने सोने-चांदी को समर्थन दिया है. वहीं, शादी-विवाह के सीजन में आभूषणों की मांग भी कीमतों को ऊपर बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है.

अहमदाबाद मंडल की 3 ट्रेनों के लिए ओटीपी प्रमाणीकरण आज से लागू

तत्काल बुकिंग प्रणाली में बदलाव

अहमदाबाद, 23 दिसंबर. पश्चिम रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार तत्काल बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया जा रहा है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो यात्री द्वारा बुकिंग के समय दिया जाएगा। ओटीपी का सफल सत्यापन होने पर ही टिकट जारी किया जाएगा।

यह ओटीपी-आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली 24 दिसम्बर, 2025 से निम्नलिखित ट्रेनों पर लागू हो जाएगी

1. ट्रेन संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर अरावली एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 19483 अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 22956 भुज-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस

अहमदाबाद मण्डल पर ओटीपी-आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली निम्नलिखित ट्रेनों पर पहले से लागू है।

1. ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 19316/19315 असारवा-इंदौर वीरभूमि एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 19489 अहमदाबाद- गोरखपुर एक्सप्रेस
4. ट्रेन संख्या 12957 साबरमती-नई दिल्ली स्वर्णजयंती राजधानी एक्सप्रेस
5. ट्रेन संख्या 12297 अहमदाबाद-पुणे दुरन्तो एक्सप्रेस
6. ट्रेन संख्या 12462 साबरमती-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
7. ट्रेन संख्या 12268/12267 हापा-मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस
8. ट्रेन संख्या 12009/12010 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी.

> नई प्रणाली कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली सभी तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे बुकिंग के समय वैध मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि OTP सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पश्चिम रेलवे सभी यात्रियों से इस महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौता भारत की बढ़ती साख का प्रमाण

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर. भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी-इंडिया) के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को एक भरोसेमंद वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती साख का प्रमाण बताया है. श्री चड्ढा ने सोमवार को घोषित इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए इस ऐतिहासिक समझौते को सम्पन्न कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एक्टा) के बाद ओशिनिया क्षेत्र में यह दूसरा ऐसा समझौता है, जो इस क्षेत्र में हमारे रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा.

एसीसी और ओरिएंट का अंबुजा में विलय मंजूर

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर. अडानी समूह की अपनी तीनों सीमेंट कंपनियों को एक साथ मिलाने की योजना के तहत एसीसी और ओरिएंट सीमेंट के अंबुजा सीमेंट में विलय के प्रस्तावों को संबंधित कंपनियों के निदेशक मंडलों की मंजूरियां मिल गयी हैं. तीन कंपनियों ने सोमवार रात शेयर बाजारों को इसकी जानकारी दी.

फिलहाल इन सौदों को शेयरधारकों और नियामकों की मंजूरियां मिलनी शेष हैं. एसीसी और ओरिएंट सीमेंट अंबुजा सीमेंट की इकाइयां हैं. फिलहाल एसीसी में अंबुजा सीमेंट की 50.05 प्रतिशत हिस्सेदारी है. एसीसी के हर शेयर धारक को 10 रुपये अंकित मूल्य के हर 100 शेयर के बदले

अंबुजा सीमेंट के दो रुपये अंकित मूल्य वाले 328 शेयर आवंटित किये जायेंगे. वहीं, ओरिएंट सीमेंट के शेयरधारकों को एक रुपये अंकित मूल्य के हर 100 शेयर के बदले अंबुजा सीमेंट के 33 शेयर आवंटित किये जायेंगे. अंबुजा सीमेंट ने बताया कि इन विलय योजनाओं के पूरा होने पर कारोबार में सुगमता आयेगी और बैलेंसशीट मजबूत होगा. तीनों कंपनियों की विनिर्माण इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखला के मिल जाने से समूह का ढांचा सरल होगा.

आईआईएम संबलपुर का विस्तार करेगा एनबीसीसी

संबलपुर 23 दिसंबर. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को ओडिसा स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर के स्थायी परिसर के चरण II अवसंरचना विकास का कार्य सौंपा गया है.

एनबीसीसी आई.आई.एम. संबलपुर के चरण - I अवसंरचना विकास कार्य को निष्पादित कर चुका है, जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 03.02.2024 को किया गया था. चरण II के विकास की लागत लगभग ?180 करोड़ होने की उम्मीद है. महत्वाकांक्षी चरण II विकास एक

भविष्योन्मुखी, एकीकृत शैक्षणिक एवं आवासीय पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना करता है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, संधारणीयता और विश्वस्तरीय परिसर आयोजना का समन्वय होगा. इस परियोजना में उन्नत कक्षाओं और संकाय केबिनों से युक्त जी+2 शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण शामिल है, साथ ही सात छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा जिसमें छह जी+5 और एक जी+3 होंगे- जो एकल एवं दोहरी आवास व्यवस्था के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि छात्रों के लिए आधुनिक और आरामदायक आवास सुविधा को सुनिश्चित करता है.

रिकॉर्ड स्तर पर भारत का निर्यात

राउंडअप 2025

वित्त वर्ष 2025 भारत के वैश्विक व्यापार इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है. आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, भारत का कुल निर्यात पहली बार 3.22 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 6 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी को दर्शाता है. यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की बदलती आर्थिक ताकत, नीति सुधारों और वैश्विक भरोसे का प्रमाण है.

इस ऐतिहासिक उछाल में सेवाओं के निर्यात की अहम भूमिका रही, जिसने 3.22 लाख करोड़ रुपये का नया रिकॉर्ड बनाया. वहीं, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों ने वस्तु निर्यात को नई ऊंचाई दी, जिससे भारत का कुल निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता से आगे बढ़कर विविध और संतुलित होता दिखा. यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ हुए नए मुक्त व्यापार समझौतों, पीएलआई योजनाओं के तहत बढ़ा घरेलू उत्पादन और रुपये की कमजोरी से मिली प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त—इन सभी ने मिलकर भारत को एक विश्वसनीय ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित किया है. आज भारत का कुल निर्यात सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है.

ओमान, न्यूजीलैंड और अन्य देशों के साथ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ने टैरिफ कम किए और भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुँच आसान बनाई. वैश्विक मांग- इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय मांग में तेज़ी आई, जिससे भारत का निर्यात बढ़ा. सरकारी नीतियां-मेक इन इंडिया और निर्यात प्रोत्साहन मिशन जैसी सरकारी पहलें उत्पादन बढ़ाने और निर्यातक कंपनियों को सहायता देने में प्रभावी रही. आरबीआई बुलेटिन (अप्रैल 2025) और प्रमुख व्यापारिक निकायों के अनुसार, इन नीतियों, वैश्विक मांग और समझौतों के संयुक्त प्रभाव ने भारत के कुल निर्यात को नए शिखर पर पहुँचाया.

गैर-पेट्रोलियम निर्यात

गैर-पेट्रोलियम वस्तु निर्यात में भी 6प्रतिशत की वृद्धि हुई. वित्त वर्ष 2025 में भारत का निर्यात 68.48 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँच गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, रसायन, वस्त्र और रत्न-आभूषण प्रमुख रहे. इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँचकर पेट्रोलियम उत्पादों के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया. फार्मास्यूटिकल्स में जेनेरिक दवाएं और टीके शामिल हैं, जबकि इंजीनियरिंग गुड्स और रसायन भी निर्यात में बढ़ोतरी में योगदान देते हैं. टेक्सटाइल उत्पाद और रत्न-आभूषण वैश्विक बाजारों में मांग में हैं. सेवाओं का निर्यात, जैसे आईटी, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन, अमेरिका और यूरोप में तेजी से बढ़ा. नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से भारत के निर्यात को और बढ़ावा मिला.गैर-पेट्रोलियम वस्तु निर्यात में भी 6प्रतिशत की वृद्धि हुई. वित्त वर्ष 2025 में भारत का निर्यात 68.48 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँच गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, रसायन, वस्त्र और रत्न-आभूषण प्रमुख रहे.

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में वृद्धि कई कारकों का परिणाम रही है

मजबूत सेवा क्षेत्र-सॉफ्टवेयर निर्यात, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और फिनटेक सेवाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई, जिससे सेवा निर्यात 345.2 बिलियन तक पहुँच गया. **विविध व्यापारिक साझेदार**-भारत ने चीन और अमेरिका से परे मध्य पूर्व, अफ्रीका और आसियान के देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत किए. **पीएलआई योजनाएं**- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा निर्यात को बढ़ावा दिया. **रुपये की कमजोरी**- रुपये के मूल्य में गिरावट से भारतीय निर्यात सस्ता और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बना. **मुक्त व्यापार समझौते**- यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ नए या संशोधित ने वस्त्र और सेवा निर्यात में योगदान दिया. वित्त वर्ष 2026 में भारत के निर्यात में मध्यम वृद्धि की संभावना आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (अप्रैल 2025) में व्यक्त की गई है. इसके मुख्य कारण हैं-वैश्विक ब्याज दरों का सामान्यीकरण- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों में स्थिरता से निर्यातकों के लिए वित्तपोषण की लागत नियंत्रित रहेगी.

बावनकुले का 'चक्रव्यूह' कामयाब!

विपक्ष चारों खाने चित, भाजपा ने बदल दिया जिले का राजनीतिक नक्शा

नागपुर. विधानसभा चुनाव के बाद नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी को जिले में बड़ी सफलता मिली है. कहा जा रहा है कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के चक्रव्यूह में पूरा विपक्ष फंस गया. बीजेपी ने विविध प्रचार अभियानों के माध्यम से काफी पहले से लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया था.

संगठन में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी. बीजेपी ने मुख्य टारगेट नई नगर परिषद व पंचायतों पर किया था जहां पहली बार चुनाव हुए. वहीं कांग्रेस व राकां के गढ़ पर भी

फिल्डिंग लगाई थी. इन चुनावों में सत्ताधारी पार्टी होने का लाभ भी मिला. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया लेकिन कांग्रेस में पूर्व मंत्री सुनील केदार, सांसद श्यामकुमार बर्वे सहित स्थानीय नेताओं की टीम ने ही कमान संभाली थी.

केदार को अपने सावनेर विस क्षेत्र में 4 में केवल मोहपा में सफलता मिली. खापा में करारी टक्कर दी लेकिन जीत नहीं मिली. 3 नप में भाजपा जीत गई.

5 जगहों पर कांग्रेस नगरसेवक अधिक

जिले भर में कांग्रेस के कुल 120 से अधिक नगरसेवक चुनकर आए हैं. ऐसी भी 5 नप-नपं हैं जहां भले ही भाजपा का नगराध्यक्ष चुना गया हो लेकिन नगरसेवकों की संख्या बीजेपी से अधिक है. गोधनी नगर पंचायत में कांग्रेस ने नगराध्यक्ष के लिए रूपाली मनोहर को खड़ा किया जो केवल 212 वोटों से हारीं लेकिन यहां बहुमत कांग्रेस का है. 17 में से 10 नगरसेवक कांग्रेस के चुने गए हैं. पूर्व जिप उपाध्यक्ष कुंदा राऊत ने यहां काफी परिश्रम किया था लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से नगराध्यक्ष पद हाथ से निकल गया.

तमिलनाडु और बंगाल में एसआईआर का फर्क

नई दिल्ली. यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि तमिलनाडु में, जहां बिहार से कम और पश्चिम बंगाल के लगभग बराबर मतदाता थे वहां दोनों राज्यों के मुकाबले ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं.

बिहार में कुल 69 लाख मतदाताओं के नाम कटे तो पश्चिम बंगाल में 58 लाख नाम कटे. लेकिन तमिलनाडु में 97 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं. यह भी हैरान करने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों के मुकाबले तमिलनाडु में मृत मतदाताओं के नाम भी ज्यादा थे. मिसाल के तौर पर बिहार में 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम कटे थे, जबकि तमिलनाडु में 26 लाख से ज्यादा मृत मतदाताओं के नाम कटे. अब सवाल है कि क्या बिहार से कम आबादी वाले तमिलनाडु में समान अवधि में बिहार से ज्यादा लोगों की मौत हुई? तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है. दूसरा सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु ने पश्चिम बंगाल की तरह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को गंभीरता से नहीं लिया?

बदला गणित तो राज्यसभा चुनाव का खेल भी पलटा!

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें जीतकर सत्ता में लौटे एनडीए ने बिहार की राजनीति का संतुलन पूरी तरह बदल दिया है. इस बहुमत का सीधा असर अप्रैल 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनावों पर दिखने वाला है, जहां बिहार से पांच सीटें खाली होंगी.

एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है और मौजूदा संख्याबल के हिसाब से एनडीए सभी पांचों सीटें अपने खाते में डाल सकती है.

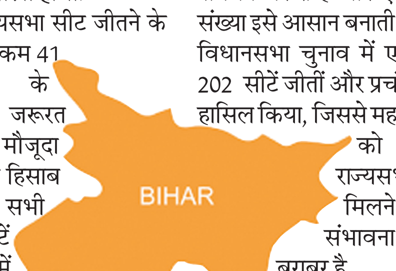

इसके उलट, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए हालात ऐसे बन गए हैं कि उनके खाते में एक भी सीट आना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है.

बता दें कि अप्रैल 2026 में खाली होने वाली राज्यसभा की 5 सीटों पर नामों की चर्चा तेज हो गई है. बिहार से कुल 16 राज्यसभा सीटें हैं और वर्तमान में आरजेडी के 5 सदस्य हैं. लेकिन, इस बार स्थिति उलट है क्योंकि एनडीए की मजबूत स्थिति से आने वाले चुनावों में सभी सीटें उनके खाते में जा सकती हैं. एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है और एनडीए की संख्या इसे आसान बनाती है. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीतीं और प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिससे महागठबंधन को एक भी राज्यसभा सीट मिलने की संभावना न के बराबर है.

महागठबंधन को शून्य पर रोकने की रणनीति- एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल 2026 के चुनावों में एक भी सीट महागठबंधन को नहीं जाने दी जाएगी. विधानसभा चुनावों के परिणामों से एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है, जहां भाजपा-जदयू और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर सरकार बनाई.

जदयू की तैयारी, दो सीटों पर फैसला जल्द

जदयू में भी 2 सीटों के लिए नामों पर मंथन जारी है. नीतीश कुमार की पार्टी अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाते हुए वफादार नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है. लोजपा (रामविलास) को मिलने वाली संभावित 1 सीट चिराग पासवान के लिए महत्वपूर्ण होगी, लेकिन इसके लिए गठबंधन के भीतर समझौता जरूरी है. कुल मिलाकर, एनडीए की योजना बिहार से राज्यसभा में पूर्ण वर्चस्व स्थापित करने की है.हालांकि, एनडीए की जीत से स्थिति साफ लगती है, लेकिन महागठबंधन की ओर से कोई रणनीतिक कदम ट्विस्ट ला सकता है.

बीजेपी कहां करेगी टीएमसी पर चोट... ममता किसे बनाएगी ढाल...

बंगाल चुनाव का रण तैयार

कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रण तैयार हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल दौरे में ममता बनर्जी सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों, भ्रष्टाचार और कट-कमीशन समेत कई मुद्दों पर घेरा.

इससे यह साफ हो गया कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दांव-पेच दो नैरेटिव के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं- कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा बनाम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे. कट्टर प्रतिद्वंद्वी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तीखी बयानबाजी में भी यही नजर आता है. इन नारों के जरिए राजनीतिक विमर्श पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं.

2021 के चुनावों के बाद से बंगाल की राजनीतिक में काफी बदलाव आया है. हावड़ा ब्रिज के नीचे से कई धाराएं बह चुकी हैं और नए मुद्दे धीरे-धीरे मुख्यधारा में आ गए हैं. इनमें अप्रवासी भारतीय और मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रमुख विवाद के मुद्दे बनकर उभरे हैं, जो टीएमसी और बीजेपी दोनों की रणनीतियों को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वे एक और कड़े चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं.

सत्ताधारी टीएमसी के तरकश में ये तीर- पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि एक करोड़ से अधिक अवैध मतदाता मौजूद हैं. यह आरोप चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के मसौदा मतदाता सूची के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद लगाया गया है. ममता बनर्जी की पार्टी ने एसआईआर विरोध को अपने प्रमुख मुद्दों में से एक बनाया है. बंगाल व उसका गौरव और भाषा के लिए संघर्ष इस बार तृणमूल के प्रमुख मुद्दों में से एक बना रहेगा. 2021 के चुनावों में भी तृणमूल ने बंगाली अस्मिता के मुद्दे को उठाया और अच्छा प्रदर्शन किया था. यही कारण है कि टीएमसी, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिकों पर कथित अत्याचारों को लगातार उजागर कर रही है.

बीजेपी कहां करेगी चोट- बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान अवैध प्रवासियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी, इसकी एक झलक शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में दिख गई. बीजेपी नेतृत्व ने इस मुद्दे पर प्रचार शुरू कर दिया है.

> ममता बनर्जी के शासनकाल में हुए घोटालों का अंबार बीजेपी के टीएमसी के खिलाफ प्रमुख मुद्दों में से एक होगा. इनमें शिक्षक की भर्ती घोटाले से लेकर कोयला और रेत खनन घोटालों तक शामिल हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है. इनमें ममता बनर्जी के करीबी मंत्रियों सहित कई टीएमसी नेता जांच के दायरे में आए हैं. बीजेपी भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को और आगे ले जाएगी.